कृषि-स्टार्टअप : चुनौतियाँ और अवसर

कृषि स्टार्टअप भारत को ज्ञान आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आधुनिक युग के आगमन के साथ, कृषि अब अतीत की पीड़ा में रहने का जोखिम नहीं उठा सकती है। एक बहुत ही अनोखे कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के फलस्वरूप, कृषि-स्टार्टअप के विकास के लिए अपार क्षमता (काफी हद तक अप्रयुक्त) और पर्याप्त अवसर हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 में किसानों को नवीनतम प्रौद्योगिकी शिक्षा देने और कार्यान्वयन में सहायता के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी में एग्रीटेक स्टार्टअप और कंपनियों की भागीदारी की घोषणा की गई थी।

डॉ जगदीप सक्सेना | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के पूर्व मुख्य संपादक। ईमेल: jgdsaxena@gmail.com

कृषि-स्टार्टअप भारत को ज्ञान-आधारित और प्रौद्योगिकी-संचालित अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। एक बहुत ही बेजोड़ कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के कारण, कृषि-स्टार्टअप के विकास के लिए विशाल क्षमता (काफी हद तक अप्रयुक्त) और पर्याप्त अवसर हैं। भारत की कृषि योग्य भूमि 156.06 मिलियन हेक्टेयर (2019) है। यह संयुक्त राज्य अमरीका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कृषि भूमि है। हमारे देश में मुख्य रूप से 15 प्रकार के कृषि-जलवायु क्षेत्र और 8 प्रकार की मिट्टी पायी जाती है, जो इसे अत्यंत विविधता से परिपूर्ण बनाते हैं। यह विविधता इसे विभिन्न प्रकार की फसलों, फलों, सब्जियों आदि को उगाने में उपयुक्त बनाती है। भारत वर्तमान में दूध, दलहन, मोटे अनाजों और जूट के साथ ही चावल, गेहूं, फलों और सब्जियों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत हाल ही में कृषि और पशुधन उत्पादों के एक प्रमुख निर्यातक के रूप में उभरा है। हालांकि, कृषि क्षेत्र भी कई जटिल समस्याओं और चुनौतियों का सामना कर रहा है। खेती में इस्तेमाल होने वाली भूमि धीरे-धीरे कम हो रही है, जो एक बड़ी चिंता का

विषय है। खेतों का आकार छोटा होने के कारण खेती की लागत बढ़ती है और आधुनिक तकनीकों को अपनाने में कठिनाई होती है। इसके कारण इनपुट के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक इस्तेमाल करने में भी कठिनाई होती है। बहुत-से किसानों को मिट्टी, मौसम, बाज़ार और अन्य विषयों के बारे में समय पर आसानी से जानकारी नहीं मिल पाती है। सामान्य तौर पर, इस तरह की समस्याओं के कारण खेती की लागत बढ़ने, संसाधनों की बर्बादी होने, फसल की हानि होने के साथ-साथ छोटे पैमाने पर उत्पादन हो पाता है। ज्यादातर कृषि-स्टार्टअप तत्काल किसानों की जरूरतों के लिए नवाचारों, प्रौद्योगिकी से जुड़े क्रियाकलापों या व्यवसाय मॉडल के माध्यम से समाधान प्रदान करने का प्रयास करते हैं। भारत सरकार के मौजूदा प्रयासों के परिणामस्वरूप, हमारे देश में अब 3,000 कृषि-स्टार्टअप हैं, जो विभिन्न कृषि क्षेत्रों और संबद्ध क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।

मोड एंड मॉडल

जनवरी 2016 में, भारत सरकार ने 19-सूत्रीय 'स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान' की शुरुआत की, जिसके परिणामस्वरूप स्टार्टअप और नवाचारों के पोषण के लिए एक मज़बूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उद्देश्य से कई नीतिगत/प्रोत्साहन संबंधी पहलों का कार्यान्वयन संभव हुआ। इसके परिणामस्वरूप कृषि सहित लगभग हर उद्योग में स्टार्टअप के निर्माण में भारी वृद्धि हुई। भौगोलिक वितरण के संदर्भ में, लगभग 60 प्रतिशत कृषि-स्टार्टअप मुख्य रूप से कुछ राज्यों के पहले और दूसरे दर्जे के शहरों में स्थित हैं। भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विश्लेषण के अनुसार, बेंगलुरु देश के स्थापित स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र हब में से एक है, इसके बाद मुंबई और दिल्ली एनसीआर का स्थान है। कृषि-स्टार्टअप को उनके फोकस क्षेत्रों, जैसे कि कृषि-तकनीक, पशुपालन, सटीक खेती, जैविक कृषि, यांत्रिक, सलाह आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कृषि स्टार्टअप आमतौर पर कृषि मूल्य शृंखला के एक या एक से अधिक चरणों में काम करते हैं। इन्हें सात व्यापक श्रेणियों - आउटपुट मार्केट लिंकेज, इनपुट आपूर्ति की सुगमता, मशीनीकरण और सिंचाई की क्षमता, वित्तीय समाधान (क्रेडिट और बीमा) की उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण रखरखाव और अनुमान-योग्य क्षमता में मदद, फसल कटाई उपरांत प्रबंधन, साजो-सामान संबंधी सेवाएँ (वेयरहाउसिंग और कोल्ड चेन) और पशुपालन गतिविधियों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ये स्टार्टअप विभिन्न प्रकार के नवाचारों और तकनीकों का उपयोग करके किसानों को समाधान प्रदान करते हैं। वे मूल्य शृंखला के विभिन्न चरणों में दक्षता में सुधार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फार्म ऑटोमेशन, सटीक कृषि, इनपुट डिलीवरी, सलाहकार बाज़ार लिंकेज आदि जैसे उत्पादों या सेवाओं का सृजन करते हैं। हाल के वर्षों में, कृषि क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय व्यवसाय मॉडल उभरे हैं। इनमें 'फार्म टू फोर्क' आपूर्ति शृंखला मॉडल, आईओटी (इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स) या बड़े डेटा-आधारित नवाचार मॉडल और अपस्ट्रीम मार्केट प्लेस मॉडल शामिल हैं। इनमें से अधिकांश कृषि-स्टार्टअप कृषि और कृषि-उद्योग की दक्षता में सुधार के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सामान्य तौर पर, डेटा डिजिटाइजेशन, एसएएएस (एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर), मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, सेटेलाइट डेटा, ड्रोन और ब्लॉक चेन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां कार्यरत हैं। कृषि-स्टार्टअप मुख्य रूप से नवाचारों या तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से मूल्य शृंखला में जटिल समस्याओं को हल करने के लिए बनाए जाते हैं। संस्थापकों के पास किफायती, तकनीकी रूप से व्यवहार्य और टिकाऊ तरीके से मुद्दों/समस्याओं के समाधान के लिए अपनी-अपनी अवधारणाएं हैं। स्टार्टअप अवधारणा से सत्यापन के चरण की ओर बढ़ते हैं, जहां चिह्नित समस्या को हल करने के लिए न्यूनतम मूल्य उत्पाद (एमवीपी) विकसित किया जाता है। सफल सत्यापन के बाद, उत्पाद को बल मिलता है, जिससे स्टार्टअप ग्राहक प्राप्त कर सकते हैं और धनोपार्जन कर सकते हैं।

हाल के वर्षों में, कृषि क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय व्यवसाय मॉडल उभरे हैं। इनमें 'फार्म टू फोर्क' आपूर्ति शृंखला मॉडल, आईओटी (इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स) या बड़े डेटा-आधारित नवाचार मॉडल और अपस्ट्रीम मार्केट प्लेस मॉडल शामिल हैं। इनमें से अधिकांश कृषि-स्टार्टअप कृषि और कृषि-उद्योग की दक्षता में सुधार के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सामान्य तौर पर, डेटा डिजिटाइजेशन, एसएएएस (एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर), मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, सेटेलाइट डेटा, ड्रोन और ब्लॉक चेन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां कार्यरत हैं। कृषि-स्टार्टअप मुख्य रूप से नवाचारों या तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से मूल्य शृंखला में जटिल समस्याओं को हल करने के लिए बनाये जाते हैं।

जब कोई स्टार्टअप धनोपार्जन शुरू करता है, तो वह स्केलिंग चरण में प्रवेश कर सकता है। हालांकि, सभी स्टार्टअप स्केलिंग चरण तक नहीं पहुँचते हैं। कई कृषि-स्टार्टअप विफल होने और गायब होने से पहले एक विस्तारित अवधि के लिए प्रारंभिक अवस्था में रहते हैं। कृषि-स्टार्टअप में विस्तार करना विशेष रूप से कठिन है, क्योंकि इसके लिए क्षेत्र परीक्षण/अनुप्रयोगों की आवश्यकता होती है। इसमें कई बाहरी कारक अपने स्वयं के अप्रत्याशित कार्यों को अंजाम देते हैं। नतीजतन, कृषि-स्टार्टअप को सबसे अधिक पोषण समर्थन/सहायता और बीज की उपलब्धता के लिए धन की आवश्यकता होती है।

नीतियां और प्रचार

एक नये कृषि-स्टार्टअप को अपने दम पर खड़े होने के लिए, विभिन्न प्रकार के संगठनों से सहायता की आवश्यकता होती है, जिसमें वित्तपोषण संस्थान, सहायक संगठन (इंक्यूबेटर, त्वरक आदि) शामिल हैं। कृषि-स्टार्टअप के निर्माण और विकास के लिए एक मज़बूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लक्ष्य के साथ, भारत सरकार ने कृषि-स्टार्टअप को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू की हैं। एग्री-बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर (एबीआई) 2015-16 में देश के विभिन्न हिस्सों में, मुख्य रूप से अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में स्थापित किए गए थे। एग्री-बिजनेस इंक्यूबेटर उभरते हुए उद्यमियों की पहचान करते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं, साझा सुविधाओं (कार्यस्थल, बुनियादी ढाँचा आदि) और उपकरण, व्यवसाय विकास, प्रौद्योगिकी, वित्त, सलाह और नेटवर्किंग सहित विभिन्न प्रकार की सेवाओं के माध्यम से उनके विकास को सुगम बनाते हैं। इंक्यूबेशन प्रक्रिया 6 से 36 महीनों तक चल सकती है, जिसमें इंक्यूबेट्स को अपने व्यवसाय मॉडल को मान्य करने और अंत में राजस्व और ग्राहकों में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है। भारत में, 100 से अधिक कृषि-केंद्रित इंक्यूबेटर हैं, जिनमें से अधिकांश भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और कृषि विश्वविद्यालयों जैसे शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में रखे गए हैं। स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय सभी इन इंक्यूबेटरों का समर्थन करते हैं।

कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने 2019-20 में, अपनी प्रमुख योजना, 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' (आरकेवीआई-रफ्तार) में 'नवाचार और कृषि-उद्यमिता विभाग' नामक एक नया घटक जोड़ा है। इस कार्यक्रम के तहत, एक चयनित स्टार्टअप अवधारणा/प्री-सीड स्टेज में 5 लाख रुपये की अधिकतम वित्तीय सहायता और सीड स्टेज में 25 लाख रुपये की अधिकतम वित्तीय सहायता के लिए पात्र है। इस संबंध में, फायर नॉलेज पार्टनर्स और 24 एग्रीबिजनेस इंक्यूबेटर्स (एबीआई) को कार्यक्रम के सुचारू और कुशल निष्पादन पर सलाह देने के लिए नियुक्त किया गया है। ज्ञान भागीदारों के रूप में, मैनेज, हैदराबाद; एनएएम, जयपुर; आईएआरआई (पूसा), नई दिल्ली; यूएएस, धारवाड़; और एएयू, जोरहाट की पहचान की गई है, जबकि एग्री-बिजनेस इंक्यूबेटर पूरे देश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों, आईआईटी और आईआईएम में स्थित हैं। इंक्यूबेटीज को एक राष्ट्रीय मीडिया प्रचार अभियान के माध्यम से चुना जाता है, जिसके बाद एक कठोर चयन प्रक्रिया होती है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों जैसे कृषि-प्रसंस्करण, खाद्य प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (आईओटी), सटीक कृषि, डिजिटल खेती आदि में परियोजनाओं के लिए अब तक कार्यक्रम द्वारा 1,100 से अधिक कृषि-स्टार्टअप का चयन और समर्थन किया गया है। कृषि-स्टार्टअप को और भी अधिक समर्थन और बढ़ावा देने के लिए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 'एग्री-हैकाथॉन'

नामक एक वार्षिक कार्यक्रम आयोजित करता है, जहां कृषि-स्टार्टअप पहचानी गई चुनौतियों और समस्याओं के लिए व्यवहार्य और अभिनव समाधान प्रदान कर सकते हैं। भारत के युवा दिमाग, रचनात्मक स्टार्टअप और चतुर नवप्रवर्तक आज भारतीय कृषि के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों के लिए नई प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान प्रस्तुत करते हैं। एक कड़ी प्रक्रिया के बाद, कृषि, प्रौद्योगिकी और विपणन के विशेषज्ञों का एक जूरी विजेताओं का चयन करता है। प्री-सीड और सीड चरणों में आकर्षक धन सहित इंक्यूबेशन समर्थन के लिए विजेता नवाचारों को पहली प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा, संबंधित फोकस क्षेत्रों में सशक्त नवाचारों को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। कृषि-हैकथॉन की सफलता के बाद अब पशुपालन, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में इसी तरह के आयोजनों की योजना बनाई जा रही है।

कृषि अनुसंधान एवं विकास के शीर्ष निकाय के रूप में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने देशभर के संस्थानों में 50 कृषि-व्यवसाय इंक्यूबेटरों की स्थापना करके नेतृत्व की भूमिका निभाई है। आईसीएआर-एबीआई, जिन्हें राष्ट्रीय कृषि नवाचार निधि परियोजना (2016-17) के तहत लॉन्च किया गया था, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों में समाधान प्रदान करने वाले स्टार्टअप्स को तकनीकी सहायता और इंक्यूबेशन सेवाएँ प्रदान करते हैं। ये केंद्र स्थायी व्यावसायिक उपक्रमों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करते हैं, साथ ही आरएंडडी लिंकेज, व्यवसाय योजना और प्रबंधन, विपणन, तकनीकी और वित्तीय मुद्दों पर सलाह/परामर्श सेवा के रूप में समर्थन भी प्रदान करते हैं। आईसीएआर-एबीआई व्यावसायीकरण के लिए अपनी मालिकाना प्रौद्योगिकियों का विपणन और प्रसार करता है, साथ ही संभावित उद्यमियों के बीच जागरुकता अभियान आयोजित करता है।

एक नये कृषि-स्टार्टअप को अपने दम पर खड़े होने के लिए, विभिन्न प्रकार के संगठनों से सहायता की आवश्यकता होती है, जिसमें वित्तपोषण संस्थान, सहायक संगठन (इंक्यूबेटर, त्वरक आदि) शामिल हैं। कृषि-स्टार्टअप के निर्माण और विकास के लिए एक मज़बूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लक्ष्य के साथ, भारत सरकार ने कृषि-स्टार्टअप को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू की हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने देशभर में राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख संस्थानों में 25 प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र (टीआईएच) स्थापित किए हैं। इनमें से तीन निर्दिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान को धरातल पर उतारने और प्रौद्योगिकी विकास करने के उद्देश्य से कृषि में इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल में शामिल हैं। आईआईटी रोपड़ का टीआईएच आईओटी- आधारित उपकरणों और सेंसर पर काम कर रहा है, जिनका उपयोग पूरे भारत में केसर के उत्पादन और आपूर्ति में किया जाएगा। आईआईटी खड़गपुर में टीआईएच फाउंडेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित सटीक कृषि तकनीकों के साथ-साथ फसल और मृदा स्वास्थ्य निगरानी के लिए पूर्वानुमान मॉडल पर काम कर रहा है। आईआईटी-बॉम्बे में आईआईएच फाउंडेशन मुख्य रूप से मिट्टी के मापदंडों की निगरानी, ड्रोन इमेजिंग और ड्रोन छिड़काव के लिए हवाई रोबोटिक्स से संबंधित है। कृषि से जुड़ी महत्वाकांक्षी स्थितियों के आधार पर बुद्धिमानी से निर्णय लेने के लिए, एक अनुमानित डेटा विश्लेषण मॉडल विकसित किया जा रहा है। उभरते स्टार्टअप्स ने किसानों या किसानों के समूहों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए अपने आसपास एक व्यवसाय मॉडल बनाने के लिए ऐसी तकनीकों में एक मज़बूत रुचि दिखाई है। 2016 से, देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-आधारित उद्यमिता और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग निधि (विकास और नवाचार का लाभ लेने के लिए राष्ट्रीय पहल) नामक एक अंब्रेला कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। निधि अपने विभिन्न घटकों के माध्यम से संचालित होती है, जो कि विचारकों और नवप्रवर्तकों को उनकी यात्रा की शुरुआत से समर्थन देने और उन्हें संपूर्ण बाज़ार मूल्य श्रृंखला से जोड़ने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। उदाहरण के लिए, निधि-प्रयास नवप्रवर्तकों और स्टार्टअप्स को अवधारणा के चरण से प्रोटोटाइप चरण तक तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है; निधि-टीबीआई स्टार्टअप्स को सफल उद्यमों में पोषित करता है; निधि-एसएसपी प्रारंभिक चरण की फंडिंग प्रदान करता है; और निधि-क्रिएट सीओई की एक विश्वस्तरीय सुविधा है, जो स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर पर जाने में मदद करती है।

निधि 36 कृषि-आधारित टीबीआई का समर्थन और प्रचार करता है, जिनमें से सात आईसीएआर- संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों में स्थित हैं। भारत सरकार ने पिछले साल एक महत्वाकांक्षी अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च किया था, जिसका लक्ष्य 10,000 अटल टिंकरिंग फोर्ब्स, 101 अटल इंक्यूबेशन सेंटर, 50 अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर स्थापित करना और अटल न्यू इंडिया चैलेंज के माध्यम से 200 स्टार्टअप का समर्थन

करना था। स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया कार्यक्रम योग्य स्टार्टअप्स को वित्त पोषण और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, जिसमें कृषि उद्यम शामिल हैं। हैंडहोल्डिंग और इंक्यूबेशन सुविधाएं स्टार्टअप्स को उनके शुरुआती चरण में मदद करती हैं।

संकल्प और निवेश

वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में नामित किया गया है, जो भारतीय उद्यमियों को वैश्विक बाज़ार में प्रवेश करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। भारत में 500 से अधिक स्टार्टअप पोषक अनाज मूल्य शृंखला में काम कर रहे हैं, जिनमें से 250 स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)-रफ्तार के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ मिलेट्स रिसर्च द्वारा इंक्यूबेट किया गया है। पोषक अनाज (श्री अन्न) की खपत को बढ़ावा देने के लिए, सरकार स्टार्टअप उद्यमियों को व्यंजनों और मूल्य वर्धित उत्पादों के रूप में सहायता कर रही है। 66 से अधिक स्टार्टअप्स को 6.25 करोड़ रुपये से अधिक दिए गए हैं, जबकि 25 स्टार्टअप को अतिरिक्त फंडिंग के लिए मंजूरी दी गई है।

केंद्रीय बजट 2022-23 में किसानों को नवीनतम प्रौद्योगिकी शिक्षा देने और कार्यान्वयन में सहायता के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी में एग्रीटेक स्टार्टअप्स और कंपनियों की भागीदारी की घोषणा की गई थी। अन्य नीतियों और कृषि-प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप के लिए ड्रोन और खेती के रूप में एक सेवा के रूप में सरकार द्वारा प्रायोजित धन की भी घोषणा की गई। नाबार्ड कृषि-प्रौद्योगिकी स्टार्टअप और ग्रामीण कृषि उद्यमों को वित्तपोषित करने के लिए एक सह-निवेश मॉडल के माध्यम से जुटाई गई मिश्रित पूँजी के साथ एक कोष की सुविधा प्रदान कर रहा है। यह योजना स्टार्टअप्स को वित्त पोषण प्रदान करती है, जो खाद्य उत्पादक संगठनों, कृषि किराये की सेवाओं और प्रौद्योगिकी निगमन का समर्थन करते हैं। सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीटेक स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान बजट (2023-24) में कृषि-केंद्रित त्वरक कोष की घोषणा की। इस कोष का उद्देश्य किसानों के लिए नवोन्मेषी और प्रभावी कृषि-प्रौद्योगिकी समाधान तैयार करना है, ताकि बाज़ार से संपर्क और उपज तक पहुँच में सुधार किया जा सके। यह कृषि पद्धतियों को बदलने और उत्पादकता और लाभप्रदता को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक तकनीक भी पेश करेगा। आर्थिक सर्वेक्षण (2022-23) के अनुसार, एग्रीटेक स्टार्टअप्स ने पिछले चार वर्षों में निजी इक्विटी निवेशकों से लगभग 6600 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए हैं, जो प्रति वर्ष 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर का संकेत है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी ने सिफारिश की है कि प्रत्येक अनुसंधान और शिक्षा संगठन कृषि उद्यमी को बढ़ावा देने के लिए एक बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करें। तालमेल कायम करने के उद्देश्य से, एक कृषि-इंक्यूबेटर निगरानी कक्ष स्थापित किया जा सकता है। यह इंक्यूबेटरों के बीच विचारों के आदान-प्रदान और महत्वपूर्ण संसाधनों को साझा करने में भी सहायता करेगा। कृषि-स्टार्टअप भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का एक महत्वपूर्ण इंजन बनने और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए तैयार हैं। ■

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र			
नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंज़िल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एस्प्लेंडेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुवनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाड़ीगुड़ा, सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बेंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2675823
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	4-सी, नेप्चून टॉवर, चौथी मंज़िल, नेहरू ब्रिज कॉर्नर, आश्रम रोड	380009	079-26588669